सभी प्रकार की सरकारी सहायताओं से मुक्त, खोजी पत्रकारिता का तेज बढ़ता अखबार

दैनिक

themovementofindia.in

द मूवमेंट ऑफ़ इंडिया

RNI No. RAJHIN/2012/48876
पोस्टल पंजीयन नं. भीलवाड़ा / 2025-2027

खोजी खबरें-तेज नजरें

प्रेरणा स्रोत - स्व. चुन्नीलाल सालवी

ये अखबार ही नहीं क्रांति का अभियान है। मानवता एवं लोकतंत्र का सजग प्रहरी, ये दुष्टों की मौत का सामान है।

वर्ष - 14 अंक -36 | बुधवार, 30 जुलाई 2025 | संपादक - दयाराम दिव्य | सहसंपादक - चाहत सालवी | मूल्य - 2 रू.

पुलिस ने तस्करों की थार का शीशा तोड़ा, बंदूक तानी

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

डोडा चूरा थार में भरकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान थार सवार नाकाबंदी तोड़ भाग निकले। करीब डेढ़ किमी आगे मोड़ पर थार फंस गई। पुलिस जवानों ने तस्करों को रोकने के लिए गाड़ी के कांच फोड़ डाले। टायर पर भी फायर किए। इसके बावजूद तस्कर भाग निकले। नाकाबंदी तोड़कर भागे मांडल थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया- पुर थाने की नाकाबंदी तोड़ कर सोमवार देर रात काले रंग की थार भाग निकली। इस थार का पीछा किया तो नाकाबंदी से डेढ़ किमी दूर थार मंदिर मोड़ के पास फंस गई। इसके बाद पीछा किया और उन्हें रुकवाने का प्रयास किया। तो तस्कर जैसे-तैसे थार को निकाल ले गए। फिलहाल तलाश जारी है।

तस्करों के आने का इनपुट था

पुलिस के अनुसार, सूचना थी कि काले रंग की थार में भारी मात्रा में डोडा-चूरा की तस्करी होनी है। इस पर पुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी करवाई थी। करीब 11:40 पर लहराते हुए एक काले रंग की थार आई और नाकाबंदी को तोड़कर भाग निकली। ऐसे में, इसकी सूचना मांडल थाने को दी और मांडल थाना पुलिस थार के पीछे लग गई।

जयपुर में बढ़े सांप काटने के मामले

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

मानसून आने के बाद शुरू हुई बारिश के साथ ही राज्य में सांप काटने के मामले तेजी बढ़ने लगे है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हर दिन 3 से 4 केस अलग-अलग हॉस्पिटलों से रेफर होकर आ रहे है। पिछले 2 माह की रिपोर्ट देखें तो स्नेक बाइट के मामले में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है।

SMS हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून और जुलाई के माह में अब तक यानी 2 माह में सांप काटने के करीब 252 केस रेफर होकर हॉस्पिटल आ चुके हैं। ये केस ज्यादातर गंभीर होते हैं। जो आसपास के ग्रामीण इलाकों या दूसरे जिलों से आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर केस पूर्वी राजस्थान के दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक के एरिया से आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि तेज बारिश में पानी भरने के कारण सांप या दूसरे जहरीले जीव-जंतु बिलों से बाहर निकलकर जमीन पर घूमते हैं। खेतों में काम करने के दौरान किसानों के साथ सांप काटने के ज्यादा केस इन दिनों सामने आते हैं। SMS मेडिकल कॉलेज के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और गणगौरी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. लिनेश्वर हर्षवर्धन का कहना है कि स्नैक बाइट के ज्यादातर मामले ग्रामीण इलाकों से आ रहे है।

राजस्थान में पुलिस का एक्शन: ऑपरेशन प्रहार में 2903 आरोपी अरेस्ट

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

राजस्थान पुलिस ने प्रदेशभर में दो दिवसीय ऑपरेशन प्रहार चलाकर अपराध की कमर तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 26 और 27 जुलाई को चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 15 हजार से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी और 2 हजार 903 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन को राज्य स्तर पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की निगरानी में अंजाम दिया गया, जो गैंगस्टरों और हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ राजस्थान पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ऑपरेशन की रणनीति पहले से ही तैयार कर ली गई थी। प्रत्येक जिले और रेंज स्तर पर पुलिस अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया। रेंज आईजी, जयपुर और जोधपुर कमिश्नर स्वयं पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद रहे, जबकि जिलों में एसपी और डीसीपी फील्ड में रहकर सीधे तौर पर कार्रवाई की निगरानी करते रहे। इस ऑपरेशन में 3104 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें 13 हजार 164 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग

लिया। इन टीमों ने प्रदेशभर में गैंगस्टर, हार्डकोर और संगीन अपराधों में वांछित अपराधियों के ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस ने 417 ऐसे कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया जो हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित थे। इसके अलावा 1688 स्थायी वारंटी और उद्घोषित अपराधियों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने 39 इनामी बदमाशों के साथ-साथ 759 सामान्य प्रकरणों में वांछित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर दो दिन की इस कार्रवाई में 2903 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बना है।

राज्य में सबसे अधिक गिरफ्तारियां जयपुर रेंज में की गई, जहां 4056 ठिकानों पर दबिश देकर कुल 916 अपराधियों को पकड़ा गया। इनमें 79 गंभीर अपराधी, 579 वारंटी, 20 इनामी और 238 अन्य आरोपी शामिल हैं। उदयपुर रेंज ने 554, अजमेर रेंज ने 501, भरतपुर ने 184, बीकानेर ने 132, जोधपुर रेंज ने 444 और कोटा रेंज ने 151 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर कमिश्नरेट ने भी अभियान में भाग लेते हुए 30 अपराधियों को पकड़ा। राजस्थान पुलिस के इस समन्वित अभियान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य में संगठित अपराध और हार्डकोर अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। %ऑपरेशन प्रहार% से न केवल अपराधियों के मन में डर पैदा हुआ है, बल्कि आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है।

भीलवाड़ा में फिर भारी बारिश की चेतावनी:मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।च आज सुबह से शहर में रिमझिम फुहार का दौर जारी है। बीते दो दिनों के लिए भी भीलवाड़ा में बारिश का अलर्ट था। लेकिन शहर में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के अलावा सूखा रहा। हालांकि बारिश नहीं होने के बाद भी मौसम सुहावना रहा, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। भीलवाड़ा सिटी के अलावा जिले के बिजोलिया, मांडलगढ़ , त्रिवेणी शाहपुरा आदि क्षेत्रों में बारिश हुई है लेकिन शहर में पिछले दिन का सूखे निकलने के बाद आज सुबह से रिमझिम फुहार ने शहर की सड़कों को भिगो दिया। आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और रुक-रुक कर हो रही रिमझिम फुहार ने मौसम को सुहावना बना दिया है। भीलवाड़ा जिले में आज ओर आने वाले दो दिन तक मौसम विभाग जयपुर ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को जिले में कही भी बारिश दर्ज नहीं हुई। आज सुबह से रिमझिम बारिश के चलते पारा भी गिरा है।

आज का अधिकतम तापमान 27 ओर न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.4 व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया।दो दिन पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 29.2 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज व कल भीलवाड़ा भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है।

सम्पादकीय

ऑपरेशन सिंदूर पर बहस

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई लंबी बातचीत न केवल स्वस्थ, सार्थक और जीवंत रही बल्कि इसने सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को उनके बेहतर रंग में देश के सामने रखा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह स्पष्ट घोषणा सामने आई कि 'दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा' जिससे वह अस्पष्टता दूर हो गई, जो इस मुद्दे को लेकर बनी हुई थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति और ऑपरेशन सिंदूर के निहितार्थों को बहुत बारीकी से स्पष्ट किया।

दुनिया को संदेश- पीएम मोदी का जवाब केवल विपक्ष के लिए नहीं था। यह सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के व्यापार रोकने की धमकी देकर सीजफायर कराने के दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले भी ट्रंप के दावों को नकार चुके हैं, लेकिन सरकार के मुखिया की तरफ से आया जवाब पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारत ऐसे फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता। संयम के साथ शक्ति- पाकिस्तान के साथ टकराव के किसी भी मोड़ पर भारत का इरादा संघर्ष बढ़ाने का नहीं था। सरकार की ओर से खुली छूट होने के बावजूद भारतीय सेना की कार्रवाई सटीक, संतुलित और गैर-उकसावे वाली थी। भारत इस लक्ष्य के साथ उतरा था कि सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आतंक के आकाओं को सबक सिखाना है। यह संयमित रुख दिखाता है कि भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, तो उसे करारा जवाब देने में संकोच नहीं करेगा।

पीएम ने डिफेंस सेक्टर में सुधार से लेकर दुनिया में भारतीय हथियारों की बढ़ती मांग तक पर सिलसिलेवार ढंग से बात रखी। उन्होंने हर उस पहलू को छुआ, जिसे लेकर हाल में बहस बढ़ी है। आमतौर पर राजनीति में मुद्दे नारों के शोर में खो जाते हैं, लेकिन पीएम के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह का जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार दिखाया उसकी सराहना की जानी चाहिए।मॉनसून सत्र का काफी वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्ष की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो। लंबी चर्चा हुई, विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए अपने सारे संदेह और सवाल सदन में रखे, सरकार ने अपने ढंग से उनके जवाब भी दे दिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सत्र के बचे हुए हिस्से में संसद में हंगामा, शोरगुल और बॉयकॉट नहीं बल्कि स्वस्थ, सार्थक चर्चा और सवाल-जवाब देखने को मिलेंगे।

प्रधान संपादक - दयाराम दिव्य

आवेदनों की त्वरित जांच हेतु अधिकारियों की नियुक्ति

सभी योजनाओं में हो रहा है त्वरित रूप से परीक्षण कार्य

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों की नीलामी के पश्चात प्राप्त आवेदनों (फॉर्म) की जांच प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक समय को ध्यान में रखते हुए पूर्व में एक समिति का गठन किया गया था। इसी संदर्भ में नगर विकास न्यास सचिव श्री ललित गोयल द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि न्यास में पदस्थापित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने प्रभारी अधिकारियों के निर्देशन में प्राप्त आवेदनों की जांच सुनिश्चित करेंगे। डॉ. अब्दुल कलाम योजना एवं नयापुर आवासीय योजना हेतु विशेषाधिकारी चिमनलाल मीणा को प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि

सहायक अभियंता पवन जीनगर उप प्रभारी होंगे। इनके साथ वरिष्ठ सहायक नरेश खटीक एवं कनिष्ठ सहायक कालूराम माली को जांच कार्य हेतु लगाया गया है।

मोहनलाल सुखाड़िया नगर एवं तिलक नगर योजना हेतु अधीक्षण अभियंता राजू बड़ारिया प्रभारी होंगे। इनके साथ सहायक अभियंता रविष श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक गोपाल तोतला एवं कनिष्ठ सहायक श्यामलाल प्रजापत को नियुक्त किया गया है।

पंचवटी योजना हेतु उपविधि परामर्शी वीना अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा रामप्रसाद जाट उप प्रभारी होंगे। उनके साथ अशीषाशी अभियंता कृष्णगोपाल नागर, सहायक प्रशासानंक अधिकारी सुरेश खोईवाल, मुंशी शिवदत्त पाठक एवं रवि त्रिपाठी कार्यरत रहेंगे। पटेल नगर योजना के लिए सहायक लेखा अधिकारी प्रथम संजय सिंघल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ सहायक अभियंता अरविंद व्यास, कनिष्ठ सहायक कुश काबरा एवं दिलीप जोशी कार्य करेंगे। पटेल नगर विस्तार योजना एवं आरपी लढ़ा योजना के लिए तहसीलदार नीरज रावत को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ सहायक अभियंता रोहन कुमार अजमेरा, वरिष्ठ प्रारूपकार शरद सारस्वत एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ को नीरज रावत के निर्देशन में लगाया गया है।

इन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संबंधित योजनाओं में प्राप्त आवेदनों की जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

अजाक एवं समता सैनिक दल ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

पिपलोदा (झालावाड़) स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे के प्रकरण में डॉ आम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान की जिला शाखा जोधपुर एवं समता सैनिक दल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अजाक जोधपुर के पदाधिकारियों ने अतिआवश्यक बैठक कर हादसे में मृत बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। समता सैनिक दल की राष्ट्रीय महासचिव कमला बुगालिया के साथ कई महिला प्रतिनिधियों ने उपस्थित रहकर संवेदना व्यक्त की तथा घटना से संबंधित मांग पत्र सौंपा। अजाक राजस्थान के उपाध्यक्ष एवं जोधपुर संभाग प्रभारी बसन्त रोयल के नेतृत्व में अजाक प्रतिनिधिमंडल द्वारा संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अजाक जोधपुर शहर के महासचिव अमरचंद रावल व अजाक जोधपुर ग्रामीण के महासचिव भागीरथ मेघवाल के साथ प्रतिनिधिमंडल में तिलोकराम ,राजेन्द्र बस्सी पाली, रानारायण थिरोदा, श्रीमती डिम्पल, विष्णु बौद्ध , अरुण कुमार, चंद्र प्रकाश

सहित कई अजाक पदाधिकारी शामिल थे। ज्ञापन में मृत बच्चों के परिजनों को 1,,1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देकर राहत देने की तथा प्रत्येक पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। घटना के पश्चात एकतरफा कार्यवाही कर शिक्षकों को निलम्बित करने के निर्णय की संगठन द्वारा पुरजोर शब्दों में निंदा की गई तथा इसे अतिशीघ्र वापस लेकर शिक्षकों की सेवाएं बहाल करने की मांग की गई। संगठन ने मांग की कि राज्य के सभी स्कूल भवनों की वर्तमान स्थिति जानकर मरम्मत योग्य कार्य अतिशीघ्र एवं कुशलता से किये जाये। तथा साथ ही नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत एक वित्तीय वर्ष में राज्य बजट में शिक्षा पर न्यूनतम 6 व्यय आवश्यक रूप से किया जाए। समता सैनिक दल भारत जिला जोधपुर प्रवक्ता मदन सालवी ओजस्वी ने इस तरह से फिर कोई कहीं पर भी हादसा ना हो इसके लिऐ सभी विधालय महा विधालयो का सर्वे कराया जाने हेतु राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया है। मृतक छात्रो के प्रति गहरी सॅवेदनाऐ प्रकट की। जोधपुर समता सेनिक दल तथा अजाक सॅगठनों आदि द्वारा दिये गये ज्ञापन के दोरान संभागीय आयुक्त ने आश्वस्त किया कि संगठन की मांगो के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जायेगा, जिससे राज्य सरकार द्वारा इस पर शीघ्र निर्णय लेकर न्यायसंगत कार्यवाही की जाएगी। ज्ञापन के पश्चात अजाक प्रदेशाध्यक्ष श्रीराम चोरड़िया से उक्त मुद्दे पर दूरभाष पर चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि संगठन द्वारा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने एवं शिक्षकों की सेवा बहाली हेतु दबाव बनाने की हर संभव कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

बन का खेड़ा मे आयुष्मान आरोग्य मन्दिर का औचक निरीक्षण एवं चरक जयंती मनाई गयी

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

आकोला (रमेश चंद्र डाड) आयुष्मान आरोग्य मन्दिर राजकीय आयुर्वेद औषधालय बन का खेड़ा आज 29 जुलाई को नाग पंचमी के अवसर पर चरक जयन्ती मनाई गयी! आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश वैष्णव ने बताया की डॉ. रमेश चंद मीणा अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय अजमेर और डॉ समय सिंह मीणा सहायक औषधि नियंत्रक अजमेर के द्वारा चरक पूजन किया गया! इस अवसर पर डॉ रमेश चंद मीणा और डॉ समय सिंह मीणा के द्वारा औषधालय का निरीक्षण किया , आवश्यक सुझाव दिये! उपरोक्त अधिकारीयो के द्वारा हर्बल गार्डन, योग स्थल, औषधियो आदि का निरीक्षण किया गया! आयुष नर्स लाड़ आचार्य, परिचारक शांता देवी,,हरू आशा धोबी एवं आशाये जुबेदा, विमला, सीमा, गायेत्री के द्वारा भी आयुष्मान आरोग्य मंदीर के बारे मे पूछा गया है! एक संगोष्टि भी आयोजित हुई जिसमे आचार्य चरक के बारे मे बताया गया!

बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेलमंगरा की दीवार जर्जर होने का खतरा - छात्राओं की सुरक्षा पर मंडरा रहा संकट

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

राजसमंद। रेलमंगरा स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी जर्जर होने के का खतरा मंडरा रहा है। विद्यालय के समीप बह रही नाली के कारण दीवार में लगातार नमी बनी रहती है, जिससे उसकी संरचना दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। वर्तमान में दीवार गिरने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

इस विषय में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार पंचायत एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया

गया, किंतु अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो गई है।

आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी एवं यूथ विंग प्रदेश संयुक्त सचिव पप्पू लाल कीर ने इस गंभीर समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा- छात्राओं की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। विद्यालय की दीवार जर्जर होने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर दीवार की मरम्मत करानी चाहिए और नाली को स्थायी रूप से कम-से-कम एक फीट दूर हटाना चाहिए, ताकि भविष्य में दीवार में नमी न बने और वह संरक्षित रह सके।

कीर ने पंचायत प्रशासन से अपील की कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और बालिका विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 - सहकारिता के क्षेत्र में मिल का पत्थर

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सहकारिता के मुख्यतः पांच सिद्धांत हैं - आत्म सहायता, आत्म जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता समता और एकजुटता। मोदी जी की सरकार ने यह अनुभव किया है कि गांवों में गरीबों, युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, सहकारिता ही एकमात्र साधन है। इसी विचार से इन्होंने ÷राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025÷ लागू की है जो सहकारी क्षेत्र के तेज, समग्र और व्यवस्थित विकास का रोडमैप है। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व वर्ष 2002 में माननीय अटल जी की सरकार में राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाया गया था। यह नीति दूरदृष्टीपूर्ण , व्यावहारिक और रिजल्ट ओरिएंटेड है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ÷सहकार से समृद्धि÷ योजना को लागू करने में सहायक होगा। यह नीति ऐसे समय में प्रतिपादित किया जा रहा है, जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहा है। सहकारिता पूरे विश्व के लिए एक आर्थिक प्रणाली है, लेकिन भारत के लिए यह जीवन का एक पारंपरिक दर्शन है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति दिनांक 24 जुलाई 2025 को मूर्त रूप ले लिया है और इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं को जोड़ना है। इस नीति से टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां बन पाएगी। सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि और हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति बनाने की योजना इस नीति में है। मोदी जी की सहकार से समृद्धि परिकल्पना के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था के तौर पर उभरेगी। आजादी के 75 साल बाद सहकारिता मंत्रालय बना है, जिससे देश की छोटी से छोटी सहकारी इकाई का सदस्य गर्व और आत्म विश्वास से भरा है।बीते चार साल में कॉपरेटिव सेक्टर हर पैमाने पर कॉरपोरेट क्षेत्र की तरह समानता के आधार पर खड़ा है। 140 करोड़ लोगों को साथ रखकर देश के अर्थ तंत्र का विकास करने की क्षमता केवल और केवल सहकारिता क्षेत्र में है। इस नीति में सहकारिता को प्रोफेशनल, टिकाऊ और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया है। यह नीति लोकतंत्र, सामुदायिक भावना और समान लाभ को बढ़ावा देती है। इस नीति द्वारा सहकारिता क्षेत्र के लिए तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए छह स्तंभ बनाए गए हैं - नींव का सशक्तिकरण, जीवंतता को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता को बढ़ावा और पहुंच का विस्तार, नए क्षेत्रों में विस्तार और सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना शामिल है। नए उभरते क्षेत्रों में सहकारी इकाइयों की भागीदारी का मतलब होगा कि सफल सहकारी इकाइयां एकजुट होकर नई सहकारी इकाई बनाएगी, जो नए क्षेत्रों में काम शुरू करेगी। इसका मुनाफा इकाइयों के माध्यम से अंततः ग्रामीण स्तर की पैक्स के सदस्यों तक पहुंचेगा। इस तरह एक बड़ा और मजबूत सहकारी इकोसिस्टम तैयार करने का लक्ष्य है। इस नीति के आधार पर वर्ष 2047 में देश की आजादी की शताब्दी तक देश का सहकारिता आंदोलन और आगे बढ़ेगा। सहकारिता में सहकार के माध्यम से आगे बढ़ेगा। पैक्स में जन औषधि के लिए 4108 पैक्स की स्वीकृति दी जा चुकी है। 393 पैक्स पेट्रोल और डीजल का आवेदन कर चुके हैं। एलपीजी के लिए 100 से अधिक पैक्स आवेदन कर चुके हैं। इतना ही नहीं हर घर नल से जल का प्रबंधन और पीएम सूर्य घर योजना आदि के लिए भी पैक्स काम करेगी। इसमें राष्ट्रीय संघों की भूमिका को भी अहम माना गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में इस ÷राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025÷ का शुभारंभ किए हैं। इस नीति को तैयार करने के लिए मंत्रालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में 40 सदस्य समिति का गठन किया था, जिसमें सहकारी संघों, विभिन्न मंत्रालयों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया था। व्यापक विचार विमर्श और क्षेत्रीय कार्यशालाओं से प्राप्त 648 सुझावों के आधार पर यह नीति तैयार की गई है जो आर बी आई, नाबार्ड के साथ परामर्श कर नीति को अंतिम रूप दिया गया है। यह नीति सहकारी क्षेत्र के समग्र और तेज विकास का रोडमैप प्रस्तुत करेगी। ÷राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025÷ ग्रामीण समृद्धि की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। देश भर में सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा और दृढ़ मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इसका औपचारिक अनावरण 24 जुलाई 2025 को किए हैं। यह नीति सहकारिता आधारित आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने, नीतिगत सुधारों की आधारशिला रखने और ग्रामीण जनों तक समृद्धि पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है जो नए भारत को ÷सहकार से समृद्धि÷ के मार्ग पर सतत रूप से अग्रसर करेगी। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का उद्देश्य है कि को-ऑपरेटिव के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाकर तथा नई उड़ान देकर एवं तकनीकी स्किल्स से लैस कर सहकारी क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाना, अनुसूचित जाति /जनजाति और दिव्यांगजनों की भागीदारी को संस्थागत रूप से सुनिश्चित करने हेतु टारगेटेड योजनाएं और बेहतर प्रतिनिधित्व, जलवायु अनुकूल खेती और सहकारी शासन, डिजिटल परिवर्तन, सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तभी हर गांव, हर युवा और हर महिला बनेगी सहकारिता की शक्ति। तकनीकी प्रशिक्षण, नेतृत्व में भागीदारी, जागरूकता अभियान और मॉडल बायलॉज के माध्यम से सहकारिता सबकी साझेदारी का माध्यम बनेगी। राष्ट्रीय सहकारी नीति महिलाओं और युवाओं को सहकारी आंदोलन का सशक्त हिस्सा बनाने हेतु व्यापक रणनीति लेकर आई है। यह नीति एक समावेशी, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में ठोस कदम है। इसका लक्ष्य वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र के जी डी पी में योगदान को तीन गुना बढ़ाना, 50 करोड़ लोगों को सहकारिता से जोड़ना, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करना है। प्रत्येक पंचायत में पैक्स का गठन, हर जिलों में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और शहरी क्षेत्र में नए अर्बन बैंक को एक सामान्य एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच पर स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करना है, जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर के अनुसूचित बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करने, दक्षता, मापनीयता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में सक्षम बनाना है। इस राष्ट्रीय सहकारिता नीति का यह भी विशेषता होगा कि अपने-अपने आधार पर सभी राज्य अपनी जरूरत के अनुरूप सहकारी नीति तैयार कर लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए आई टी ढांचा और सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल रोजगार मंच बनाया जाएगा। इस नीति के तहत सहकारी समितियों से दालों, मिलेट्स, मक्का और तिलहनों का उत्पादन और खरीद को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स किसानों को जलवायु के अनुकूल फसल चक्र और सौर पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सहकारी समितियां को ODOP योजना और GeM-ONDC जैसे प्लेटफार्म से जोड़कर बेहतर बाजार पहुंच के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 ÷विकसित भारत 2047÷ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही इस नीति में मोदी जी की सरकार ने कानून में संशोधन कर राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 तैयार की है जो 24 जुलाई 2025 से लागू हो गया है। श्री अमित शाह जी ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तहत प्रत्येक राज्य की सहकारी नीति उस राज्य की सहकारी परिस्थितियों के अनुसार तैयार की जाएगी और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जिससे भारत स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक आदर्श सहकारी राज्य बन सकता है। मोदी जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय की रचना की है जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना और विकास को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी बनाना है। यह सहकारी नीति आने वाले 25 साल तक सहकारिता क्षेत्र को प्रासंगिक बनाएगी, योगदान देने वाला बनाएगी और भविष्य का क्षेत्र भी बनाएगी।

इस परिपेक्ष्य में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध होगा कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मेरे विचार से केंद्र और प्रदेश में सहकारिता आयोग÷का गठन किया जाना आवश्यक है। सहकारिता आयोग के गठन से प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी और किसी भी अड़चन अथवा लाल फीताशाही को दूर करने में आयोग समर्थ रहेगी, जिससे राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के प्रभावी होने में निश्चित रूप से सहायक हो पाएगी। बिहार में सहकारिता आयोग के गठन हेतु ज्ञापन श्री प्रणव कुमार, माननीय विधायक, मुंगेर विधान सभा, मुंगेर को दी गई थी। इन्होंने दिनांक 24.07.2025 को बिहार विधान सभा में ध्यानाकर्षण में सहकारिता आयोग गठन हेतु प्रस्ताव समर्पित किए हैं।

जय सहकारिता।

दीपक कुमार,
वरीय अधिवक्ता

राजस्थान नर्सेज यूनियन नर्सेज अब नहीं काटेंगे केक, नई पहल की करी शुरुआत

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

राजस्थान नर्सेज यूनियन भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने बताया की पूरा राजस्थान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम हरियालो राजस्थान के तहत माँ के नाम पेड़ लगा रहा है उसी से प्रेरित होकर आज मंगलवार को दोपहर 12.15 बजे नर्सिंग अधीक्षक दुर्गा लाल मीणा के सानिध्य मे गिरिराज लढ्ढा के जन्म दिन उपलक्ष पर 11 पेड़ लगाकर प्रण लिया की अब किसी भी नर्सेज का जन्मदिन यूनियन केक काटकर नहीं अपितु माँ के नाम पेड़ लगाकर मनाएंगे यूनियन के जिला प्रवक्ता गिरिराज लढ्ढा ने बताया की हरित क्रांति की इस नई शुरुआत जो भीलवाड़ा महात्मा गाँधी हॉस्पिटल के नर्सेज ने की है उसकी जितनी सराहना की जाये कम है मुकुटराज सिंह नर्सेज को मरीजों की परम सेवा करने के सौभाग्य प्राप्ति के जीवन मिलने की बधाई देते हुवे कहा की मरीजों की सेवा और उच्चतम गुणवत्ता से उनका इलाज करें और जीवन को सार्थक करें

द्य कार्यक्रम विश्व हिन्दू परिषद् के विभाग मंत्री विजय ओझा की प्रेरणा और मार्गदर्शन मे किया गया द्य इस अवसर पर कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक बीजू कुमार, , पूर्व अधीक्षक अनिल छाजेड, नर्सिंग कार्यालय से लीला शर्मा, विना फिलिप, महिला प्रमुख अनीता चौधरी,लैब डिपार्टमेंट से अरविन्द सनाढ्य, उदयराम धूमस, ओम प्रकाश रेगर, × हड्ड4 डिपार्टमेंट से इंचार्ज घनश्याम असावा, फार्मेसी डिपार्टमेंट से इंचार्ज अंकित काबरा,नीरज व्यास, खुशबू माहेश्वरी, पूर्व यु आई टी तहसीलदार गंगापाल जीनगर, कार्यकारी अध्यक्ष ललित जीनगर, आई डिपार्टमेंट से विनोद सिंगल,सर्जिकल से अंकित काबरा, ग्रामीण अध्यक्ष अमित व्यास, सुमंत शर्मा, सुनील कोटडी, निखिल विश्नोई,सहित कई नर्सेज उपस्थित थे

रोड लाइट बंद होने की शिकायत पर लाइट को ही खोलकर ले गए

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

पुर। उपनगर पुर के वार्ड नंबर 1 ग्यारस माता कॉलोनी के नाहर गली के बाहर खंबे पर लगी रोड लाइट बहुत दिनों से खराब हो रही थी जिसकी शिकायत नगर निगम के ऑफ़िस में करवाई गई लेकिन निगम के कर्मचारी रोड लाइट को ठीक करने की बजाय लाइट को ही खोलकर ले गए। इस संबंध में कई बार नगर निगम ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी लाइट वापस नहीं लगाई गई है जिससे रात के समय अंधेरा बना रहता है और दुर्घटना की आशंका रहती है। निगम के कर्मचारियों की इस लाइट चोरी का कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आखिर इस रोड लाइट को खोलकर कौन ले गया है ?।

उपनगर पुर में कई जगह रोड लाइट बंद रहती हैं सूचना देने के उपरांत भी समय पर चालू नहीं किया जा रहा है। कई जगह रोड लाइट का टाइमिंग बिगड़ा हुआ है जो रात को कभी भी बंद हो जाती है तथा दिन में चलती रहती हैं।

द मूवमेंट ऑफ इंडिया
खोजी पत्रकारिता
का तेज बढ़ता अखबार

क्या आप भी जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं ? ये हैं फायदे एवं नुकसान

एक तो लोगों को नौकरी मिलना आज के समय में बेहद मुश्किल का कार्य है, वहीं कई लोग भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें एक नौकरी छोड़ने से पहले ही दूसरी नौकरी मिल जाए! ऐसे में थोड़ी ग्रोथ के लिए लोगबाग जल्दी-जल्दी नौकरी चेंज करने लगते हैं। शायद आप भी उनमें से हों, किन्तु अगर आप भी जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करते हैं तो यह जान लें कि शार्ट टर्म में बेशक इसके कुछ फायदे दिखें, किन्तु दीर्घावधि में इसका काफी नुक्सान होता है।

हालांकि अभी के समय में हालात यह हैं कि अब पहले की तरह लोग एक ही नौकरी पर बहुत दिन तक कार्य नहीं करते हैं, बल्कि नौकरी चेंज करने में वह अपनी ग्रोथ देखते हैं, और उसी अनुरूप डिसीजन भी लेते हैं।

किंतु जॉब बदलने का फैसला कुछ मामलों में बेशक ठीक लगता है, किंतु कुछ मामलों में यह कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आइये जानते हैं,अगर फायदे की बात करें तो आप यह जान लीजिए कि जॉब बदलने में सबसे पहले तो कुछ परसेंट ही सही, मगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके काम के अधिक से अधिक पैसे मिलें, और एक नौकरी में अगर उस अनुरूप ग्रोथ नहीं होती है, तो वह जॉब बदलना चाहता है, और ऐसे में उसे तुरंत ही ग्रोथ मिल जाती है।

वहीं अगर दूसरे फायदे की बात करें तो इससे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका नेटवर्क बेहतर होता है। अगर एक कंपनी में आप जॉब करते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, और इस तरीके से अलग-अलग कंपनी में आपका बेस तैयार होता चला जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कंपनी में काम करने पर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आपकी स्किल कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जाती है, तो दूसरी कंपनी में जब आप जाते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है। चाहे वहां आपका नया सीनियर हो, चाहे वहां का इनवायरमेंट हो, आप उस कंपनी से नई चीजें जरूर सीखते हैं, और यह वह चीज है जो आपको आने वाले दिनों में मजबूती करती है। इसके अलावा कई भारत लोग एक जगह पर कार्य करने से बोर भी हो जाते हैं, ऐसे में नयी जॉब में उन्हें नयापन भी मिलता है।

हालांकि यह इसका पॉजिटिव पक्ष है, किंतु कुछ निगेटिव पक्ष भी हैं, जिन्हें आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

नुकसान की बात करें तो बार बार जॉब चेंज करने से पोजीशन के मामले में आपके आगे बढ़ने पर असर पड़ सकता है। जी हाँ! एक ही कंपनी में जब आप काम करते हैं, तो वहां आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होती है। वहां आपको प्रमोशन मिलता रहता है, किंतु जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो सीनियर पोजिशन पर आपको पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है।

इससे आपकी लॉयल्टी भी चेक की जाती है। अगर आप कुछ ज्यादा ही जॉब चेंज करते हैं, तब आपको किसी हायर पोजिशन पर जॉब देने से एचआर मैनेजर निश्चित ही कई बार सोचेगा। कंपनी अगर किसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर आप की हायरिंग कर भी लेती है, तो भी कंपनी श्योर नहीं हो पाती है कि आप आखिर कितने दिन जॉब करेंगे? कहीं आप बीच में ही जॉब छोड़ कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे? ऐसे में आप शक के घेरे में आ जाते हैं!

यह कार्य सिर्फ पोजीशन के मामले में ही नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के मामले में भी है, तो क्लाइंट इंटरेक्शन के मामले में भी है। जब तक आप किसी कंपनी के लम्बे समय तक वफादार नहीं होते हैं, तब तक किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमांड आपके हाथ में देने से निश्चित रूप से वह कंपनी हिचकिचाएगी। इसी प्रकार से बड़े क्लाइंट हैंडलिंग में भी कंपनी आपको तब तक इंवॉल्व नहीं करेगी, जब तक आप उसके प्रति लॉयल साबित न हो जाएँ! ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाओं से आपके दूर रहने की शुरुआत हो जाती है।

कंपनी बार-बार चेंज करने का आपके फाइनेंसियल पोजीशन पर भी खासा असर पड़ता है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप होम लोन या दूसरे लोन के लिए अप्लाई करें,आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर चेक की जाती है। आप किस कंपनी में कितने लंबे समय तक रहे हैं, यह आपके लिए एक प्लस प्वाइंट साबित होता है। वहीं अगर आप बार-बार अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप की फाइनेंसियल स्टेबिलिटी पर एक सवाल खड़ा होता है।

मैनेजेरियल स्किल डेवलपमेंट पर पड़ता है फर्क

जी हां! ऊपर से आपको बेशक लगे कि आप कुछ चीजें ऊपर ऊपर समझ गए हैं, किंतु प्रबंधन के गुणों को आप तब तक नहीं समझ सकते, जब तक आप किसी कंपनी में देर तक नहीं टिकेंगे! कहीं टिक कर काम करने के बाद ही कंपनी पॉलिटिक्स, प्रबंधन टेक्निक आप समझ पाते हैं। कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस प्रकार लेती है, वास्तव में उसकी रुचि और भविष्य की योजनायें क्या हैं, यह आप गहराई से एक समय के बाद ही समझ पाते हैं। अगर बाद में आप कभी अपना उद्यम शुरू करना चाहें, तो इसलिए जरूरी है कि किसी कंपनी में आप देर तक टिक कर काम करें, अन्यथा आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे।

पॉलीमर साइंस में बीटेक करने के बाद है शानदार करियर संभावनाएं

विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलीमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं।

मौजूदा तकनीकी दौर में पॉलीमर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इनमें प्लास्टिक, मोल्डेड सामग्री, सिंथेटिक फाइबर, रबर आदि शामिल हैं। ईको-फ्रेंडली और रीसाइक्लेबल प्लास्टिक के साथ इन सभी पॉलीमर प्रोडक्ट्स के उचित प्रबंधन की आवश्यकता भी समय के साथ बढ़ रही है। यह काम पॉलिमर इंजीनियर्स करते हैं। वे प्लांट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन और थर्मोडाइनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलीमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं। आज के इस लेख में हम आपको पॉलीमर साइंस में बीटेक के बाद करियर अवसर के बारे में जानकारी देंगे-

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के अवसर

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद आप सरकारी फर्मों जैसे सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला और सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि में बतौर जूनियर रिसर्च फेलो काम कर सकते हैं। इन फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कम से कम 55% अंकों के साथ एम।टेक डिग्री प्राप्त करने के बाद कोई भी नेट के लिए बैठ सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी बी टेक डिग्री में 60% अंक प्राप्त किए हैं, वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक या इंजीनियर के रूप में 40,000/- रुपये के मासिक वेतन के साथ काम कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी वैज्ञानिक बी पद की भूमिका में पॉलिमर इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती करता है। इनके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) जैसे संगठन भी पॉलिमर इंजीनियरिंग में बी टेक स्नातकों को नियुक्त करते हैं। इनके अलावा स्नातक डिग्री धारक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑयल इंडिया लेबोरेटरीज, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग प्लांट्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (ओएनजीसी) आदि विभागों में भी रोजगार पा सकते हैं। उम्मीदवार विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में लेक्चरर पद का विकल्प भी चुन सकते हैं।

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद निजी क्षेत्र के अवसर

जर्मन आधारित कंपनी विंडमोलर एंड होल्शर, अक्सर अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुभाग में संचालन करने के लिए पॉलिमर इंजीनियरों की भर्ती करती है। 7 से 8 साल के कार्य अनुभव वाले लोग एलाइड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स/बिजनेस डेवलपमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आप 35,000/- से रु 150,000/- प्रति माह तक की सैलरी पा सकते हैं। अपोलो टायर्स लिमिटेड, सिएट लिमिटेड आदि जैसी टायर कंपनियों को भी पॉलिमर इंजीनियर्स की जरूरत है। पॉलीमर इंजीनियरिंग में स्नातकों के लिए क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर्स/ टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलीमर स्पेशलिस्ट आदि सामान्य जॉब प्रोफाइल हैं।

प्रतिभावान विद्यार्थियों को तराशती योजना
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

नेशनल टेलेंट सर्च यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनसीईआरटी की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना और उनकी प्रतिभा को बढ़ाना है। इसके तहत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन और विधि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना प्रतिभावान विद्यार्थियों को मासिक स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक मदद दे कर सहयोग देती है। इस योजना में बेसिक साइंस, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों के लिए पीएचडी स्तर तक सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन एवं विधि के लिए पीजी स्तर तक सहायता दी जाती है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कक्षा 8 स्तर पर किया जाता है।

स्कॉलरशिप

परीक्षा आयोजन के आधार पर कक्षा 8 की परीक्षाओं के लिए बैठे छात्रों के प्रत्येक समूह के लिए 1000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं। स्कॉलरशिप की राशि प्रत्येक माह 500 रुपए होती है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत और विकलांग छात्रों के लिए 3 प्रतिशत स्कॉलरशिप आरक्षित होती है। स्कॉलरशिप का भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता को न देकर संबद्ध संस्थान के प्रमुख के माध्यम से दिया जाता है।

चयन प्रक्रिया

प्रतिभाओं की पहचान दो स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है। प्रथम स्तर का चयन अलग-अलग राज्य/यूनियन टेरेटरीज द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रथम स्तर की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही एनसीईआरटी द्वारा संचालित द्वितीय स्तर की परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र माने जाते हैं। राज्य और यूनियन टेरेटरीज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना की प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा के साथ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की भी परीक्षा आयोजित करते हैं।

पात्रता

मान्यताप्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी उस राज्य/यूनियन टेरेटरी द्वारा संचालित प्रथम स्तर की परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं, जिस राज्य में विद्यालय स्थित है।

आवेदन प्रपत्र

आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने के लिये राज्य संपर्क अधिकारी से संपर्क करें। आवेदन-प्रपत्र एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन प्रपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तथा प्रपत्र कहां जमा कराया जायेगा, इस संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के संपर्क अधिकारी से पता किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों की आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां भिन्न हो सकती हैं।

शुल्क

एनसीईआरटी द्वारा द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। राज्य और यूनियन टेरेटरी प्रथम परीक्षा के लिए अपेक्षित शुल्क के भुगतान के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इसलिये आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले कितनी और कैसे फीस दी जायेगी, इसका पता अपने राज्य संपर्क अधिकारी से लगा लेना चाहिए।

परीक्षा माध्यम

परीक्षा हिन्दी व अंग्रेजी के साथ असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में संचालित की जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में जिस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उस विकल्प का उल्लेख करें। इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को उस भाषा में प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी।

परीक्षा-विधि

8वीं के लिए लिखित परीक्षा की विधि इस प्रकार है :-प्रथम स्तर की राज्य/ यूनियन टेरेटरी स्तर पर संचालित परीक्षा में दो भाग होंगे (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी)। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परीक्षा में (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी) शामिल होंगे। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। (स) इंटरव्यू - इंटरव्यू के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संचालित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा में प्रथम भाग एमएटी और द्वितीय भाग एसएटी शामिल होंगे। दोनों परीक्षाएं एक छोटे से अंतराल पर अलग-अलग ली जाएंगी। मानसिक योग्यता परीक्षा-एमएटी - चार विकल्पों सहित इसमें 90 मल्टीच्वॉइस प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। समय 90 मिनट होगा।

स्कॉलरशिप पाने की सामान्य शर्त

स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो। वह अच्छा आचरण बनाए रखता हो (संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित) और अपना अध्ययन एक नियमित विद्यार्थी के रूप में कर रहा हो। बिना उचित अवकाश के अनुपस्थित न होता हो। पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करता हो। कोई रोजगार नहीं करता हो। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना पीएचडी कोर्स को छोड़ कर छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोई अन्य स्कॉलरशिप स्वीकार करने से वंचित नहीं करती, अलबत्ता किसी भी पाठ्यक्रम के लिए विदेश में अध्ययन के लिए कोई स्कॉलरशिप उपलब्ध नहीं होगी। यदि कोई प्राप्तकर्ता पंजीकरण/प्रवेश के एक माह के अंदर अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ता है तो उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी।

विजुअल मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र में हैं अपार संभावनाएं

विजुअल मर्चेंडाइजिंग शब्द भले ही कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन सेल्स और एडवरटाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोग इससे भली-भांति वाकिफ हैं। विजुअल मर्चेंडाइजिंग वास्तव में एक आर्ट है, जिसमें एक व्यक्ति किसी प्रॉडक्ट या सर्विस को क्लाइंट्स के सामने कुछ इस तरह पेश करता है ताकि वह सेल्स को बढ़ावा दे सके। अब इस कॉन्सेप्ट को रिटेल सेक्टर में एक मार्केटिंग टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में वह सभी गतिविधियां शामिल हैं, जो रिटेल स्टोर्स में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रॉडक्ट के संभावित ग्राहकों के माइंड को समझना और उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में शिक्षित करना व प्रॉडक्ट को बेहद इफेक्ट व क्रिएटिव तरीके से पेश करना आदि। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस करियर के बारे में

क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग

एजुकेशन एक्सपर्ट बताते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विजुअल मर्चेंडाइजर कहा जाता है। विजुअल मर्चेंडाइजर ऐसे पेशेवर हैं जो किसी भी ब्रांड, एक चेहरे को देने के लिए जिम्मेदार हैं। वे ऑनलाइन शॉपर्स और रिटेल स्टोर दोनों के लिए विंडो और स्टोर डिस्प्ले में अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन करते हैं। वे स्टोर थीम की योजना बनाते हैं, डिस्प्ले के लिए प्रॉपर की व्यवस्था करते हैं, डिस्प्ले फिक्स्चर और लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं, ओपनिंग से पहले स्टोर सेट करते हैं, फ्लोर प्लान के साथ काम करते हैं और डिस्प्ले को बनाने के लिए सेल्स फ्लोर पर स्टोर कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं। एक विजुअल मर्चेंडाइजर का मुख्य उद्देश्य स्टोर की छवि के अनुरूप डिस्प्ले बनाना और अधिक ग्राहकों को स्टोर में लाना है।

शैक्षणिक योग्यता

आजकल ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग से संबंधित सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। इस कोर्स को करने के लिए छात्र का 12वीं पास होना आवश्यक है। हालांकि अधिकतर जगहों पर विजुअल मर्चेंडाइजिंग को फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स के तहत पढ़ाया जाता है।

कॅरियर एक्सपर्ट के अनुसार, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के कोर्स में छात्रों को विजुअल मर्चेंडाइजिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है जैसे कि रिटेल स्टोर का लेआउट और डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन, स्टोर के अंदर फर्नीचर और फिक्स्चर की स्थापना, स्टोर डिस्प्ले और उत्पादों की प्रस्तुति, विभिन्न संचार साधनों के उपयोग के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करना।

व्यक्तिगत गुण

इस क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों में डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के गुण का होना बेहद आवश्यक है। एक विजुअल मर्चेंडाइजर में बेहतरीन आर्गनाइजिंग स्किल्स होने के साथ-साथ प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व टाइम मैनेजमेंट आदि विशेषताएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा उनमें संचार व इंटरपर्सनल स्किल्स, समस्या सुलझाने की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है। कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजर को उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को जानना आना चाहिए और उसे रुझानों का भी पूर्वानमान लगा लेना चाहिए।

संभावनाएं

शॉपिंग मॉल, फाइव स्टार होटल, बुटीक व रिटेल आउटलेट्स की संख्या बढ़ने के साथ ही विजुअल मर्चेंडाइजर्स की मांग में भी काफी इजाफा हुआ है। विजुअल मर्चेंडाइजर फैशन बुटीक, शॉपिंग मॉल, एम्पोरिया, डिजाइन कंपनी, आर्किटेक्चर फर्म, थीम पार्टी ऑर्गनाइजिंग कंपनी आदि में जॉब कर सकते हैं। वे प्रदर्शनियों, मेलों, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, अवार्ड सेरेमनी, मॉल, रिटेल में विंडो डिस्प्ले के लिए अनुबंध के आधार पर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में एक फ्रेशर भी दस से पंद्रह हजार आसानी से कमा सकता है। वहीं कुछ समय के अनुभव के बाद आप किसी बड़े ब्रांड के रिटेल आउटलिट में काम कर सकते हैं और एक आकर्षक पैकेज पा सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बैंगलोर
- द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई
- स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, कोच्चि
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक दयाराम दिव्य द्वारा मुद्रक वेदांत प्रभाकर, मेधा कम्प्यूटर्स एंड ऑफसेट प्रिंटर्स, ऑफिस नं. 128, वार्ड नं. 25, नंदभवन कांवाखेड़ा पार्क के पास, भीलवाड़ा 311001 (राज.) से मुद्रित एवं एस-20, प्रतापनगर, भीलवाड़ा (राज.) से प्रकाशित। संपादक दयाराम दिव्य 96949 57624, 87695 58132 * PRB एक्ट के तहत ख़बरों के चयन के लिए उत्तरदायी। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भीलवाड़ा होगा